आर. एन. आई. नं. UPHIN/2010/32566 डाक. पंजीयन. संख्या– SSP/LW/NP-311

अद्भुत समाचार

निष्पक्ष एवं निर्भीक हिन्दी साप्ताहिक

हर ख़बर पर पैनी नज़र

वर्ष : 17 अंक : 17 लखनऊ, शुक्रवार 07 अगस्त 2026 सा 13 अगस्त 2026 तक पृष्ठ–8 मूल्य : एक रूपया

प्रधानमंत्री मोदी–नेतन्याहू की पश्चिम एशिया पर बात, भारत–इजराइल साझेदारी की समीक्षा की

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर चर्चा की। बातचीत के दौरान, पीएम मोदी और नेतन्याहू ने भारत–इजराइल स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप (विशेष रणनीतिक साझेदारी) में हो रही लगातार प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के आपसी फायदे के लिए अलग–अलग क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेता नियमित रूप से संपर्क में रहने और आपसी हित के मुद्दों पर बातचीत जारी रखने पर भी सहमत हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने

फरवरी में इजराइल का दौरा किया था, जहाँ उन्हें भारत–इजराइल संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए इजराइली संसद के सर्वोच्च सम्मान 'मेडल ऑफ द नेसेट' से सम्मानित किया गया था। इससे पहले नेतन्याहू ने इजराइल की विदेश नीति में भारत के महत्व पर जोर दिया था। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमारे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक बताया और कहा कि उनकी सरकार नई दिल्ली के साथ संबंध मजबूत करने में भारी निवेश कर रही है। नेतन्याहू ने इजराइल के लिए और गठबंधन बनाने की जरूरत पर जोर दिया और इसी संदर्भ में भारत का भी जिक्र किया। यह बात अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के उस बयान के कुछ दिनों बाद कही गई, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका इजराइल का इकलौता शक्तिशाली सहयोगी है।

मुख्यमंत्री योगी ने की नई युवा नीति की समीक्षा, युवाओं की आकांक्षाओं के अनुरूप नीति तैयार करने के दिए निर्देश

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य की एकीकृत युवा नीति को सूबे के युवाओं की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप तैयार किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक

मुख्यमंत्री ने कहा है कि युवा नीति तैयार करने से पहले प्रदेश के १६ से ३५ वर्ष के युवाओं की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को समझा जाएगा और उसके बाद ही नीति को आकार दिया जाएगा। आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश की युवा नीति शिक्षा, कौशल, रोजगार, स्वास्थ्य और नेतृत्व विकास को एकीकृत करेगी। बयान के मुताबिक, आदित्यनाथ ने युवाओं के समग्र विकास की निगरानी के लिए विशेषज्ञों का स्वतंत्र आयोग बनाने की जरूरत पर जोर देते हुए 'सरदार वल्लभभाई पटेल औद्योगिक एवं रोजगार जोन' की स्थापना शीघ्र प्रारम्भ करने के भी निर्देश दिये। आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग योजना को और प्रभावी बनाने तथा हर विश्वविद्यालय और महाविद्यालय तक इसके विस्तार पर विचार करने को भी कहा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को 'सरदार वल्लभभाई पटेल औद्योगिक एवं रोजगार जोन' की स्थापना की प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। उनका मानना है कि इससे युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग योजना को और अधिक प्रभावी बनाने तथा इसे प्रदेश के प्रत्येक विश्वविद्यालय और महाविद्यालय तक विस्तारित करने की संभावनाओं पर विचार करने के निर्देश भी दिए।

प्रदर्शनकारियों के साथ राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस

नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले छात्रों व युवाओं के साथ तीसरी प्रेस क न्फ्रेंस की है। उन्होंने इससे पहले पैलेट गन से घायल साहिल लोचब के साथ और फिर सीपीआई

माले के छात्र संगठन आईसा की तीन छात्राओं के साथ प्रेस क न्फ्रेंस की थी। बुधवार की प्रेस क न्फ्रेंस में चार प्रदर्शनकारी शामिल हुए। इसमें राहुल ने कहा कि २० जुलाई को हुए क करोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर लाठी व पैलेट गन से हमला किया गया। राहुल ने आरोप लगाया कि १५ साल की एक छात्रा के घर गुंडे भेजे गए और उससे जबरन माफी मंगवाई गई। राहुल के साथ प्रेस क न्फ्रेंस में मौजूद एक छात्रा ने कहा, 'भारत माता की जय बोलने पर हमें देशद्रोही कहा गया। हम शांति से चल रहे थे तो एक पुलिस अफसर ने शरीर के ऊपरी हिस्से पर मारा'। राहुल गांधी ने कहा, 'प्रदर्शनकारियों ने कुछ भी गलत नहीं किया। इनका लगातार शोषण हो रहा है। ये बच्चे देश के भविष्य के लिए लड़े। इन्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं। लोकतंत्र के लिए ये बच्चे लड़े, इसके लिए इनका ध न्यवाद'। राहुल ने मीडिया से कहा, 'हमने प्रदर्शन कर रहे कुछ युवाओं से बात की। उन्होंने बताया कि उनके साथ मारपीट की गई, ध मकाया गया और दबाव बनाया गया। मुझे उन पर और देशभर के हजारों युवाओं पर गर्व है। उन्होंने संविधान, भारत के विचार और देश के भविष्य की रक्षा की है'। राहुल गांधी ने आगे कहा, 'पहले छात्रों के घर गुंडे भेजना, १५ साल की एक लड़की से जबरन माफी मंगवाना और फिर उस माफी को स्वीकार करना पूरी तरह बेतुका है। हम इसे स्वीकार नहीं करते'। राहुल के साथ मुंबई की रिया अहीर भी प्रेस क न्फ्रेंस में थीं। शिवाजी पार्क प्रदर्शन के दौरान पुलिस की गाड़ी के सामने खड़ी होने वाली रिया अहीर ने कहा, 'मैं वो लड़की हूं, जिसने मुंबई पुलिस को रोका था। मैं कहना चाहूंगी कि मैं वो लड़की हूं, जिसने २० बच्चों को गैरकानूनी हिरासत में जाने से रोका था। मेरी अपील है कि ंपया नैरेटिव को बदलें। जो भी मैंने किया, उसकी वजह से मुझे बहुत परेशान किया जा रहा है'।

लखनऊ में सनसनीः सालेह नगर चौराहे पर लावारिस कार से मिला युवक का शव, इलाके में मचा हड़कंप

लखनऊ।'' राजधानी के आशियाना थाना क्षेत्र स्थित सालेह नगर चौराहे पर गुरुवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब कई घंटों से लावारिस खड़ी एक ''स्विफ्ट डिजायर कार (न्च ३३ ठठ ८६८६)'' से तेज दुर्गंध आने पर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही आशियाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची। जांच के दौरान कार के अंदर ''एक युवक का शव'' मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना फैलते ही घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही घटनास्थल की फोरेंसिक जांच

कराई जा रही है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। वाहन के मालिक और मृतक की पहचान करने के प्रयास भी जारी हैं। ''फिलहाल युवक की मौत के कारणों का आधिकारिक खुलासा नहीं हुआ है।'' पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत के कारणों तथा घटना की परिस्थितियों का स्पष्ट पता चल सकेगा।

सम्पादकीय

लोकतंत्र की आवाज और जंतर–मंतरः क्या विरोध की जगह और दूर होगी?

भारत का लोकतंत्र केवल चुनावों से नहीं, बल्कि नागरिकों के असहमति प्रकट करने के अधिकार से भी मजबूत होता है। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन लोकतांत्रिक व्यवस्था का अभिन्न अंग हैं और भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को अपनी बात रखने, सरकार से सवाल पूछने तथा नीतियों के विरोध में आवाज उठाने का अधिकार देता है। ऐसे में यदि विरोध प्रदर्शनों के लिए निर्धारित स्थानों को लेकर नई सीमाएं तय करने की कोशिश होती है, तो यह केवल प्रशासनिक विषय नहीं रह जाता, बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता से जुड़ा गंभीर प्रश्न बन जाता है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में दायर एक जनहित याचिका ने इसी बहस को फिर से जीवित कर दिया है। याचिका में मांग की गई है कि नई दिल्ली के जंतर–मंतर के बजाय रामलीला मैदान को राजधानी का प्राथमिक विरोध–प्रदर्शन स्थल घोषित किया जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने इस याचिका को महत्वपूर्ण मामला मानते हुए केंद्र सरकार से इस संबंध में अपना पक्ष रखने को कहा है। अदालत ने अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं दिया है, लेकिन इस मामले को सुनवाई के लिए स्वीकार किए जाने से ही व्यापक चर्चा शुरू हो गई है। चिंता का विषय यह है कि पिछले कुछ वर्षों में जंतर–मंतर पर विरोध–प्रदर्शनों को लेकर पहले से ही कई प्रकार की प्रशासनिक पाबंदियां लागू की जा चुकी हैं। यदि भविष्य में इसे प्राथमिक प्रदर्शन स्थल के रूप में और सीमित कर दिया जाता है, तो इसका सीधा प्रभाव नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पड़ सकता है। लोकतंत्र में विरोध की आवाज केवल दर्ज होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका सत्ता और नीति–निर्माताओं तक प्रभावी ढंग से पहुंचना भी उतना ही आवश्यक है। इतिहास पर दृष्टि डालें तो आजादी के बाद लंबे समय तक नई दिल्ली का बोट क्लब देशभर के आंदोलनों और जनसभाओं का प्रमुख केंद्र रहा। संसद भवन और राष्ट्रपति भवन के निकट होने के कारण वहां आयोजित प्रदर्शन सीधे सत्ता प्रतिष्ठान तक अपनी बात पहुंचाने का माध्यम बनते थे। लेकिन १९९० के दशक में सुरक्षा और कानून–व्यवस्था के तर्कों के आधार पर वहां विरोध प्रदर्शनों पर रोक लगा दी गई और जंतर–मंतर को वैकल्पिक स्थल के रूप में विकसित किया गया। तब भी अनेक लोकतांत्रिक समूहों ने इसे विरोध की आवाज को सत्ता से दूर ले जाने वाला कदम माना था। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार दिल्ली पुलिस १,००० से कम प्रतिभागियों वाले प्रदर्शनों के लिए जंतर–मंतर और उससे अधिक लोगों की उपस्थिति वाले आयोजनों के लिए रामलीला मैदान की अनुमति देती है। इस व्यवस्था का उद्देश्य सुरक्षा और यातायात प्रबंधन बताया जाता है। हालांकि, जंतर–मंतर की संसद से निकटता के कारण प्रदर्शनकारियों के लिए अपनी मांगों को सीधे जनप्रतिनिधियों और सरकार तक पहुंचाने का अवसर उपलब्ध रहता है। यही कारण है कि अनेक सामाजिक, राजनीतिक और कर्मचारी संगठनों ने वर्षों से जंतर–मंतर को अपनी आवाज का प्रमुख मंच बनाया है। हाल के कुछ प्रदर्शनों के दौरान सरकार और प्रशासन को असहज परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। माना जा रहा है कि इसी पृष्ठभूमि में जंतर–मंतर की भूमिका को लेकर फिर से बहस तेज हुई है। हालांकि किसी एक घटना के आधार पर विरोध के पूरे लोकतांत्रिक ढांचे में बदलाव करना उचित नहीं माना जा सकता। कानून–व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन उसके नाम पर नागरिक अधिकारों को अनावश्यक रूप से सीमित करना लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नहीं होगा। यह भी उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय स्वयं वर्ष २०१८ में इस विषय पर स्पष्ट टिप्पणी कर चुका है। उस समय अदालत ने जंतर–मंतर से प्रदर्शनकारियों को रामलीला मैदान भेजने संबंधी आदेश को निरस्त करते हुए कहा था कि जंतर–मंतर या बोट क्लब जैसे स्थानों पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। न्यायालय ने माना था कि शांतिपूर्ण विरोध संविधान द्वारा संरक्षित मौलिक अधिकारों का हिस्सा है और प्रशासन का दायित्व नागरिक अधिकारों तथा सार्वजनिक व्यवस्था के बीच संतुलन स्थापित करना है, न कि किसी एक पक्ष को पूरी तरह समाप्त कर देना। लोकतंत्र में विरोध केवल सरकार की आलोचना का माध्यम नहीं होता, बल्कि नीतियों में सुधार, जनभावनाओं की अभिव्यक्ति और शासन को जवाबदेह बनाए रखने का भी प्रभावी साधन है। यदि विरोध के मंचों को लगातार सत्ता से दूर ले जाया जाएगा, तो यह आशंका स्वाभाविक है कि जनता और सरकार के बीच संवाद की दूरी भी बढ़ेगी। लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती इस बात में है कि सरकार आलोचना को सुनने और असहमति को स्थान देने की क्षमता बनाए रखे। सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में जो भी अंतिम निर्णय दे, उससे पहले संविधान की मूल भावना, नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक परंपराओं को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए। विरोध प्रदर्शन की स्वतंत्रता केवल प्रदर्शनकारियों का अधिकार नहीं, बल्कि एक जीवंत लोकतंत्र की पहचान भी है। इसलिए आवश्यक है कि ऐसे किसी भी निर्णय में सुरक्षा और व्यवस्था के साथ–साथ नागरिकों के उस संवैधानिक अधिकार की भी पूरी रक्षा हो, जिसके माध्यम से उनकी आवाज संसद और सरकार तक प्रभावी ढंग से पहुंच सके।

योगी ने अनुच्छेद ३७० हटाने के निर्णय को बताया भारत की एकता का स्वर्णिम अध्याय

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुच्छेद ३७० हटाए जाने की सातवीं वर्षगांठ पर कहा कि पांच अगस्त, २०१९ भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के इतिहास का स्वर्णिम दिवस है तथा इस निर्णय से 'एक विधान, एक निशान, एक प्रधान' के स्वप्न और 'एक भारत–श्रेष्ठ भारत' के राष्ट्रीय संकल्प को ऐतिहासिक सिद्धि मिली। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर जारी अपने संदेश में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के दृढ़ संकल्प से अनुच्छेद ३७० की समाप्ति का ऐतिहासिक निर्णय संभव हो सका। उन्होंने कहा कि यह निर्णय श्रद्धेय डॉ.

श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस राष्ट्रनिष्ठ स्वप्न की पूर्णता है, जिसके लिए उन्होंने अपना सर्वस्व राष्ट्र के चरणों में समर्पित कर दिया था। योगी ने कहा कि पिछले सात वर्षों में जम्मू–कश्मीर ने आतंकवाद से शांति, अलगाववाद से एकात्मता और अस्थिरता से विकास की ऐतिहासिक यात्रा तय की है। आज जम्मू–कश्मीर नए भारत की आकांक्षाओं, प्रगति और समृद्धि का सशक्त प्रतीक बन चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र प्रथम की भावना से ओत–प्रोत इस युगांतरकारी निर्णय के लिए वह प्रधानमंत्री श्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह के प्रति हार्दिक आभार एवं अभिनंदन व्यक्त करते हैं। उन्होंने कामना की कि माँ भारती का मस्तक सदा ऊँचा रहे।

यूपी में १८ आधुनिक बस स्टेशनों के विकास का बड़ा मौका, १,१०० करोड़ से अधिक निवेश के लिए यूपीएसआरटीसी ने मांगी निविदाएं

लखनऊ, ५ अगस्त। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवहन अवसंरचना को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएस आरटीसी) ने पीपीपी (पब्लिक–प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल के तहत प्रदेश के १८ आधुनिक प्रीमियम बस स्टेशनों एवं वाणिज्यिक परिसरों के विकास के लिए निविदाएं आमंत्रित की हैं। इन परियोजनाओं में १,१०० करोड़ से अधिक निवेश की संभावना जताई गई है। बस स्टेशनों को आधुनिक यात्री सुविधाओं से लैस करने के साथ–साथ यहां होटल, रिटेल स्पेस, फूड कोर्ट, ऑफिस स्पेस, मल्टीप्लेक्स और अन्य व्यावसायिक सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। इससे बस स्टेशन आधुनिक ट्रांजिट–कमर्शियल हब के रूप में विकसित

होंगे। योजना के तहत निवेशकों को ६० वर्ष तक की कंसेशन अवधि का प्रावधान दिया गया है, जिससे उन्हें दीर्घकालिक और स्थिर व्यावसायिक अवसर प्राप्त होंगे। यूपीएसआरटीसी के अनुसार निविदा जमा करने की अंतिम तिथि १० अगस्त २०२६, दोपहर २ बजे निर्धारित की गई है। इच्छुक निवेशक यूपीएसआरटीसी की आधिकारिक वेबसाइट तथा उत्तर प्रदेश ई–टेंडर पोर्टल पर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इन परियोजनाओं के अंतर्गत अकबरपुर, अमेठी, बदायूं, भिनगा, गोंडा, बलरामपुर, बस्ती, गोला, सिधौली, माती, उन्नाव, हैदरगढ़, नहटौर, सराय अकिल, बादशाहपुर, तरवा, पीलीभीत और निचलौल में आधुनिक बस स्टेशनों का विकास किया जाएगा। इससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलने के साथ स्थानीय स्तर पर व्यापार, निवेश और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

योगी सरकार का बड़ा फैसलाः यूपी में तीन नए निजी विश्वविद्यालयों को मिली संचालन की मंजूरी, युवाओं को मिलेंगे उच्च शिक्षा के नए अवसर

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रदेश में तीन नए निजी विश्वविद्यालयों के संचालन को मंजूरी दे दी है। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर गाजियाबाद, कानपुर और फतेहपुर में स्थापित होने वाले विश्वविद्यालयों के प्रबंधन को शसंचालन प्राधिकार पत्रश (अनुज्ञा पत्र) सौंपे। प्रदेश में स्थापित होने वाले नए विश्वविद्यालयों में अजय

कुमार गर्ग विश्वविद्यालय, महर्षि महेश योगी इंटरनेशनल एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय तथा ठाकुर युगराज सिंह विश्वविद्यालय शामिल हैं। इन विश्वविद्यालयों के शुरू होने से उच्च, तकनीकी और कृषि शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसर उपलब्ध होंगे तथा विद्यार्थियों को अपने क्षेत्र में ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१९ में संशोधन अध्यादेशों के तहत इन विश्वविद्यालयों को विधिवत स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने संबंधित संस्थाओं से शासन के सभी मानकों और नियमों का पालन करते हुए रोजगारपरक, आधुनिक और मूल्य आधारित शिक्षा उपलब्ध कराने की अपेक्षा जताई। उन्होंने कहा कि योगी सरकार प्रदेश में निजी निवेश को बढ़ावा देकर उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रही है। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश को उच्च शिक्षा और अनुसंधान का अग्रणी केंद्र बनाना तथा विद्यार्थियों को विश्वस्तरीय शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना है।

घुमंतू समाज को अब सम्मान और विकास का अधिकार मिलेगा, मुख्यमंत्री योगी ने घुमंतू विकास बोर्ड को बताया ऐतिहासिक पहल

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को कहा कि उत्तर प्रदेश में 'घुमंतू विकास बोर्ड' के गठन के बाद घुमंतू समाज के लोगों को दर–दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा और सरकार उन्हें सम्मानजनक जीवन का अधिकार दिलाने और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करेगी। प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा 'घुमंतू विकास बोर्ड' के गठन के निर्णय के बाद घुमंतू समाज को ओर से आयोजित आभार एवं अभिनंदन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बोर्ड का गठन बिना जाति, क्षेत्र, भाषा अथवा किसी प्रकार के भेदभाव के प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने की सोच की नई कड़ी है। उन्होंने कहा, ''घुमंतू विकास बोर्ड केवल एक प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह वर्षों से उपेक्षित घुमंतू समाज को न्याय, सम्मान और अवसर दिलाने का सशक्त माध्यम बनेगा। ''मुख्यमंत्री ने कहा कि अंग्रेजों ने १८७१ के श्अपराधी ठहराने वाला आदिवासी कानूनश (क्रिमिनल ट्राइब एक्ट) के माध्यम से उन वीर समुदायों को अपराधी घोषित कर दिया था, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा कि १८५७ के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के बाद अंग्रेजों ने सुनियोजित षड्यंत्र के तहत इन जातियों को कलंकित किया ताकि उनका सामाजिक सम्मान समाप्त हो जाए। आदित्यनाथ ने कहा कि स्वतंत्र भारत में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर ने इस अन्याय को समाप्त करते हुए इन समुदायों को 'विमुक्त जाति' का सम्मान दिलाया था मगर उनके समुचित विकास के लिए अपेक्षित प्रयास लंबे समय तक नहीं किये गये। मुख्यमंत्री ने कहा कि गत वर्ष घुमंतू समाज के सम्मेलन में उनके समक्ष बोर्ड गठन की मांग रखी गई थी और उन्होंने उसी समय इसकी घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि अब बोर्ड के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और इसकी संरचना ऐसी होगी जिसमें विभिन्न घुमंतू एवं विमुक्त जातियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो। इस मौके पर प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने कहा कि विमुक्त एवं घुमंतू समाज के कल्याण केउन्होंने कहा कि यह बोर्ड विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं को विमुक्त एवं घुमंतू समाज तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने का सेतु बनेगा और उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन लाएगा। अरुण ने कहा कि लोग कहने लगे हैं कि यह समाज अब घुमंतू नहीं, टिकंतू हो रहा है। अब उनके पास अपना घर है, बिजली है, आजीविका के साधन हैं और सम्मान के साथ आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। लिए घुमंतू विकास बोर्ड के गठन का निर्णय ऐतिहासिक एवं दूरदर्शी है।

यूपी के परिषदीय स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को मिलेगी नई उड़ान, हर विकासखंड में तैयार होंगे मास्टर ट्रेनर

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार परिषदीय विद्यालयों में स्थापित स्मार्ट क्लास, ICT लैब और डिजिटल शिक्षण संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड में मास्टर ट्रेनर तैयार किए जाएंगे, जो शिक्षकों को तकनीक आधारित शिक्षण का व्यावहारिक प्रशिक्षण देंगे। इसका उद्देश्य कक्षा शिक्षण को अधिक रोचक, सहभागितापूर्ण और गुणवत्तापूर्ण बनाना है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक मोनिका रानी ने इस संबंध में सभी जिलों को विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किए हैं। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल स्कूलों में स्मार्ट क्लास स्थापित करना नहीं, बल्कि प्रत्येक शिक्षक को डिजिटल शिक्षण में दक्ष बनाना है। उन्होंने कहा कि तकनीक आधारित शिक्षा से कक्षाएं अधिक रोचक, सहभागितापूर्ण और

गुणवत्तापूर्ण बनेंगी तथा यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति–२०२० के अनुरूप डिजिटल शिक्षा को मजबूत आधार प्रदान करेगी। मोनिका रानी ने सभी जिलों को प्रशिक्षण संबंधी विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किए हैं। प्रत्येक विकासखंड से एक शिक्षक को मास्टर ट्रेनर के रूप में नामित किया गया है। राज्य स्तरीय प्रशिक्षण पूरा होने के बाद अब ये प्रशिक्षक अपने–अपने विकासखंडों में शिक्षकों को दो दिवसीय प्रशिक्षण देंगे। प्रत्येक प्रशिक्षण बैच में अधिकतम ५० शिक्षक शामिल होंगे। प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्री–टेस्ट, पोस्ट–टेस्ट, ऑनलाइन मॉनिटरिंग और एस्केलेशन मैट्रिक्स की व्यवस्था की गई है। तकनीकी सहायता के लिए विद्या समीक्षा केंद्र एवं सेवा प्रदाताओं का सहयोग भी उपलब्ध रहेगा। प्रदेश सरकार ने सभी जिलों को ३० अगस्त २०२६ तक ब्ल क स्तर पर प्रशिक्षण अभियान पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसकी निगरानी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, डायट, खंड शिक्षा अधिकारी और जिला समन्वयकों द्वारा की जाएगी, ताकि डिजिटल शिक्षा को विद्यालयों की नियमित शिक्षण प्रक्रिया का प्रभावी हिस्सा बनाया जा सके।

बेसिक विद्यालय अलीनगर सुनहरा में सड़क सुरक्षा का पाठः जागरूकता अभियान व चित्रकला प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों ने दिया सुरक्षित यातायात का संदेश

लखनऊ। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और बच्चों में यातायात नियमों के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करने के उद्देश्य से बेसिक विद्यालय अलीनगर सुनहरा में गुरुवार को सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए सुरक्षित यातायात का संकल्प लिया और सड़क सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण नियमों की जानकारी प्राप्त की। कार्यक्रम के दौरान विशेष प्रशिक्षक सुमित मिश्रा ने विद्यार्थियों को सड़क पर सुरक्षित चलने, ट्रैफिक संकेतों का पालन करने, हेलमेट एवं सीट बेल्ट के महत्व तथा पैदल यात्रियों के नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल नियमों का पालन भर नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की सामाजिक जिम्मेदारी भी है। जागरूकता अभियान में ४६ विद्यार्थियों ने सहभागिता करते हुए सुरक्षित यातायात का संकल्प लिया। इसके उपरांत आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में भी ४६ छात्र–छात्राओं ने अपनी रचनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। बच्चों ने रंगों और चित्रों के माध्यम से सड़क सुरक्षा से जुड़े प्रभावी संदेश प्रस्तुत किए, जिनमें हेलमेट पहनने, यातायात संकेतों का पालन करने तथा सड़क पर सावधानी बरतने का संदेश प्रमुख रहा। विद्यालय परिवार ने बताया कि इस प्रकार के रचनात्मक एवं सहभागितापूर्ण कार्यक्रमों का उद्देश्य विद्यार्थियों में प्रारंभिक अवस्था से ही यातायात नियमों के प्रति जागरूकता विकसित करना है, ताकि वे स्वयं सुरक्षित रहें और समाज में भी सड़क सुरक्षा के प्रति सकारात्मक संदेश का प्रसार कर सकें। कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों ने सड़क सुरक्षा नियमों का सदैव पालन करने तथा अपने परिवार और आसपास के लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करने का संकल्प लिया।

डीजीपी राजीव कृष्ण ने पिता हरिकिशन मित्तल को दी मुखाग्नि, भारी बरसात के बीच पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक

लखनऊ। डीजीपी राजीव कृष्ण ने गुरुवार को अपने दिवंगत पिता हरिकिशन मित्तल के पार्थिव शरीर

का भैंसाकुंड में दाह संस्कार किया। भारी बरसात के बीच यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मुख्यसचिव एसपी गोयल सहित शासन और पुलिस के आलाधिकारी अंतिम दर्शन के लिए मौजूद रहे। इस दौरान डीजीपी के परिजन और रिश्तेदार भी पहुंचे हुए थे। प्रशासन ने नेताओं, शासन और पुलिस के अधिकारियों के बैठने के लिए टेंट और कुर्सियां लगवाई थी। भीड़ अधिक होने के कारण भैंसाकुंड के चारों तरफ बैरिकेडिंग लगाना पड़ा, जिससे यातायात आंशिक रूप से बाधित रहा। डीजीपी राजीव कृष्ण, उनकी पत्नी मीनाक्षी सिंह, सरोजनीनगर विधायक राजेश्वर सिंह एवं नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह शव वाहन से पार्थिव शरीर को लेकर भैंसाकुंड पहुंची। इस बीच भैंसाकुंड में पहले से मुख्यसचिव एसपी गोयल, डीजी इंटेलीजेंस अमरेंद्र कुमार सेंगर, सदस्य मानवाधिकार आयोग ब्रजभूषण शर्मा, एडीजी कानून–व्यवस्था अमिताभ यश, एडीजी जोन लखनऊ प्रवीण त्रिपाठी, अपर महाधिवक्ता वीके शाही सहित कई आलाधिकारी मौजूद थे। बरसात होने की आशंका के चलते भैंसाकुंड में टेंट आदि लगा दिया गया था। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह गोप एवं शंकरी सिंह भी मौके पर पहुंच डीजीपी एवं उनके परिजनों को धांधस बंधाया। १२ बजे के आसपास डीजीपी राजीव कृष्ण ने पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। इस मौके पर पूर्व डीजीपी एके जैन, डीजी डीके ठाकुर, डीजी जेल पीसी मीना, आईएएस अभिषेक प्रकाश, लखनऊ के पुलिस कमिश्नर तरुण गॉबा सहित कई आलाधिकारी मौजूद रहे।

Gen Z राष्ट्र–विरोधी नहीं, बातचीत जरूरीः मोहन भागवत बोले- शिक्षा प्रणाली में सुधार की जरूरत

नई दिल्ली। देश के अलग–अलग हिस्सों में पेपर लीक को लेकर **Gen Z** (नई पीढ़ी) के बढ़ते विरोध के बीच, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को कहा कि उनकी शिकायतें जायज हैं और भारत की शिक्षा प्रणाली में सुधार की जरूरत है। हाल ही में छात्रों के विरोध–प्रदर्शन और प्रदर्शनकारियों को 'राष्ट्र–विरोधी' कहे जाने पर **RSS** प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि अगर **Gen Z** विरोध कर रहा है, तो वे राष्ट्र–विरोधी नहीं हैं। वे हमारे ही लोग हैं, हमारी अगली पीढ़ी हैं।

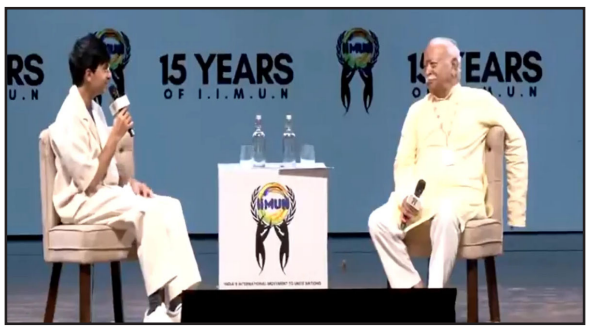

मुझे नहीं लगता कि ळमदर ऐसी है। मुझे लगता है कि नई पीढ़ी– **Gen Z** और **Gen Alph**ा –हमारी मौजूदा पीढ़ी से ज्यादा ईमानदार है, और देशभक्ति व सेवा की सच्ची अपील उन पर असर करती है। भागवत ने कहा कि लोकतंत्र में, सहमति बनाने का एक तरीका विरोध भी है। कई तरह के विचार सामने आते हैं और बातचीत के जरिए सहमति बनती है। अगर अलग–अलग वजहों से बात नहीं सुनी जाती, तो आंदोलन किया जा सकता है। लेकिन ऐसा सहमति बनाने के लिए किया जाना चाहिए, न कि बंटवारा करने के लिए। जहाँ तक **Gen Z** की बात है, हाल ही में जो हुआ–उनकी शिकायत सही है। भारत की शिक्षा व्यवस्था में बहुत कुछ करने की जरूरत है, और ऐसा नहीं हो रहा हैय इसलिए यह मुद्दा उठाया जा रहा है। तो, सच में बातचीत होनी चाहिए... **Gen Z** के बारे में मेरे अनुभव की बात करें तो, जब हम उनकी उम्र के थे, तो हम बड़ों की बात मान लेते थे, कभी सवाल नहीं उठाते थे। उन्होंने आगे कहा कि अब, **Gen Z** और **Gen Alph**ा सवाल पूछते हैं, उन्हें तार्किक जवाब और प्यार चाहिए... लोकतंत्र में यही तरीका है। इसे अंग्रेजी में 'डिबेट' कहते हैं, हम इसे 'शास्त्रार्थ' कहते हैं – वहाँ कोई बहस नहीं होती, बल्कि दो पक्ष होते हैं: 'पूर्व' और 'उत्तर'। हम सभी पहलुओं को देखते हैं और हर किसी का अपना नजरिया होता है, इसलिए हर विषय पर एक नया पहलू सामने आता है। तो, हमें कई राय और विरोधी राय मिलती हैं, जो मिलकर सच्चाई की पूरी तस्वीर बनाती हैं। ऐसा जरूर होना चाहिए। भागवत ने कहा कि मैं यह नहीं कहूँगा कि **Gen Z** को विरोध नहीं करना चाहिए, लेकिन लोकतंत्र में विरोध करने और काम करने के कुछ तरीके होते हैं। संविधान बनाने वालों ने, और डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर के भाषणों में, इस बारे में संकेत दिए गए हैं। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। हमें यह भी देखना चाहिए कि **Gen Z** विरोध करने के लिए आवाज नहीं उठा रही है, वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें कुछ दिक्कतें हैं और उन्हें ठीक किया जाना चाहिए। आंदोलन मेरे या आपके खिलाफ नहीं, बल्कि सिस्टम को सुधारने के लिए होना चाहिए। एक कार्यक्रम में बोलते हुए भागवत ने कहा कि उन्हें पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हालिया टकराव के सही हालात के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन युवाओं पर उनका भरोसा अटूट है। भागवत ने कहा कि मैं 'जेन जेड' (**Gen Z**) पर आँख बंद करके भरोसा करूँगा। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें देश के युवाओं की नीयत और उनकी आकांक्षाओं पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा कोई कमर्शियल बिजनेस नहीं है। समुदाय की मदद से शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सकता है। शिक्षा का आर्थिक बोझ बहुत ज्यादा है। हमें सतर्क और सक्रिय रहने की जरूरत है और सिस्टम का नियमित रूप से आकलन करना होगा। हमें अपने शिक्षकों को भी प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। शिक्षा देना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है।

होर्मुज जलडमः मध्य जल्द खुलेगा, अन्यथा ईरान पर होगा बड़ा हमला : ट्रंप

नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि होर्मुज जलडमः मध्य जल्द ही खोल दिया जाएगा, अन्यथा ईरान पर "बहुत बड़ा" हमला किया जाएगा। फॉक्स न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने ईरान के साथ वार्ता की प्रगति संबंधी सवाल पर कहा, "होर्मुज जलडमरूमध्य बहुत जल्द खोल दिया जाएगा, अन्यथा उन्हें बहुत कड़ा प्रहार झेलना पड़ेगा। किसी भी स्थिति में जलडमःमध्य खुलने वाला है। फॉक्स न्यूज के अनुसार, श्री ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता फिर शुरू हो गयी है तथा होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को समाप्त करने संबंधी समझौता "बहुत जल्द" होने वाला है। ईरानी अधिकारियों ने अमेरिका के साथ किसी भी प्रत्यक्ष वार्ता में शामिल होने से इनकार किया है। उनका कहना है कि बातचीत ओमान के माध्यम से मध्यस्थों के जरिए हो रही है। उल्लेखनीय है कि श्री ट्रंप ने रविवार को कहा था कि संभावित शांति समझौते की संभावना को देखते हुए उन्होंने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमले रद्द कर दिए थे। उनके अनुसार इस समझौते की रूपरेखा में होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े मुद्दों पर सहमति शामिल है।

ढाका लौटेंगी शेख हसीना

नई दिल्ली। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने वतन ढाका लौटने का ऐलान किया है। भारत आने के दो साल बाद उन्होंने पहली बार अपने मुल्क के लोगों को संबोधित किया और भावुक होते हुए कहा कि वे दो साल से अपने देश को पीड़ित होते देख रही हैं। उन्होंने कहा कि यह वो बांग्लादेश नहीं है, जिसके लिए १९७१ में ३० लाख लोगों ने अपने जीवन का बलिदान किया। वर्चुअल तरीके से दिए गए गए अपने भाषण में उन्होंने कहा कि वे इस साल दिसंबर में अपने देश लौट सकती हैं। करीब २५ मिनट के अपने भाषण में शेख हसीना ने कहा है बांग्लादेश के नए शासक शेख मुजीब उर रहमान की विरासत मिटा देना चाहते हैं। भाषण के दौरान उनका कैमरा बंद रहा। यानी उनकी सिर्फ आवाज सुनी गई। बताया जा रहा है कि सुरक्षा कारणों से ऐसा किया गया। खबर है कि उनके संबोधन के दौरान बांग्लादेश के क्रिकेटर शकीबुल हसन भी मौजूद थे। इस वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट क्लब ऑफ साउथ एशिया की ओर से किया गया था। गौरतलब है कि दो साल पहले पांच अगस्त को ही बांग्लादेश में तख्तापलट हुआ था, जिसके बाद शेख हसीना भारत आ गई थीं। बहरहाल, शेख हसीना ने अपने भाषण में कहा, 'मुझे पता है कि वे मुझे जेल में डाल सकते हैं या मार भी सकते हैं, फिर भी मैं बांग्लादेश वापस जाउंगी। लोगों का समर्थन मेरे लिए बहुत जरूरी है'। उन्होंने आगे कहा, 'मौत की सजा, झूठे मुकदमे और दिखावटी सुनवाई मुझे डरा नहीं सकती। मेरे खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाई गैरकानूनी, असंवैधानिक और राजनीतिक मकसद से प्रेरित है'। हसीना ने यह भी कहा कि उन्होंने अपनी इच्छा से बांग्लादेश नहीं छोड़ा था। प्रदर्शनकारियों के प्रधानमंत्री आवास की ओर बढ़ने पर उनके पास वहां से निकलने के लिए सिर्फ ३० से ४० मिनट का समय था। तब उन्हें नहीं पता था कि वे देश छोड़ कर जा रही हैं। वह अपने पैतृक गांव तुंगीपाड़ा जाने की तैयारी कर रही थीं, लेकिन हालात ऐसे बने कि देश छोड़ना पड़ा। गौरतलब है कि उनके भारत आने के बाद से बांग्लादेश उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है। बहरहाल, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री ने भारत को मित्र देश बताते हुए कहा कि वह हमेशा बांग्लादेश का अच्छा दोस्त रहा है। उन्होंने कहा, 'जब भी बांग्लादेश किसी मुश्किल हालात में होता है, भारत हमेशा उसके साथ खड़ा रहता है, चाहे वह १९७१ हो, १९७५ हो या आज का समय'। हसीना ने कहा कि सरकारों के बीच के संबंध अलग हो सकते हैं, लेकिन भारत हमेशा से एक अच्छा दोस्त रहा है और मुझे पता है कि वह आगे भी ऐसा ही रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि भारत भले ही मित्र देश है लेकिन उन्हें अपने लोगों के पास जाना है।

सीजेपी पार्टी नहीं प्रेशर ग्रुप रहेगा

मुंबई। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने अपने संगठन की दो दिन की बैठक से पहले बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि वे कोई राजनीतिक दल नहीं बनाएंगे। उन्होंने कहा है कि उनका संगठन प्रेशर ग्रुप की तरह काम करेगा। दीपके ने यह भी ऐलान किया कि वे झारखंड जाएंगे और पेपर लीक व परीक्षा की दूसरी गड़बड़ियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों को अपना समर्थन देंगे। संभाजीनगर में दो दिन की बैठक से पहले दीपके ने बुधवार को कहा, 'क करोच जनता पार्टी फिलहाल राजनीतिक पार्टी नहीं बनेगी। अभी भारत को एक मजबूत प्रेशर ग्रुप की जरूरत है, इसलिए क करोच पार्टी उसी भूमिका में काम करेगी'। उन्होंने आगे कहा, 'अगर हम राजनीतिक पार्टी बनाते, तो हमारा आंदोलन सफल नहीं होता। आंदोलन इसलिए सफल हुआ, क्योंकि अलग अलग विचारधाराओं और राजनीतिक दलों के लोग लोकतंत्र को कमजोर करने वाली चीजों के खिलाफ एक साथ आए। आज भारत को किसी नई राजनीतिक पार्टी की नहीं, बल्कि एक मजबूत जन आंदोलन की जरूरत है'। बैठक शुरू होने से पहले मीडिया से बातचीत में दीपके ने बताया कि इसमें जंतर मंतर आंदोलन की समीक्षा, ई–२० पेट्रोल, शिक्षा व्यवस्था जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि बैठक में यह भी तय किया जाएगा कि संगठन को देश भर में कैसे मजबूत किया जाए। अभिजीत दीपके ने यह भी कहा कि सीजेपी झारखंड जाएगी और वहां आंदोलन कर रहे छात्रों के साथ खड़ी रहेगी। हम झारखंड के छात्रों की हर मांग का समर्थन करते हैं। सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि छात्र प्रदर्शनकारियों पर दर्ज एफआईआर वापस कराने की मांग को लेकर सरकार से बातचीत चल रही है। घायल प्रदर्शनकारियों को कानूनी और मेडिकल मदद देने की भी तैयारी की जा रही है। सौरव ने बताया कि सोनम वांगचुक संगठन के मेंटर बने रहेंगे और संगठन समय समय पर उनसे सलाह लेगा।

सरकार ने मांगा कांग्रेस का सहयोग

नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र के तीसरे हफ्ते में भी कामकाज नहीं हो पा रहा है। विपक्ष के हंगामे की वजह से किसी भी बिल पर चर्चा नहीं हो रही है। हालांकि सरकार एक के बाद एक बिल पास करा रही है। इस बीच खबर है कि महिला आरक्षण और परिसीमन के मसले पर सरकार संसद का तीन दिन का विशेष सत्र बुला रही है। इस बार १६ से १८ अगस्त की तारीख चुनी गई है। गौरतलब है कि १६ से १८ अप्रैल को भी सरकार ने विशेष सत्र बुलाया था लेकिन संविधान संशोधन का बिल पास नहीं हो सका था। बहरहाल, विशेष सत्र की चर्चा के बीच बुधवार को संसदीय कार्य मंत्री कीरेन रिजिजू ने कांग्रेस से सहयोग मांगा। उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा से भी मिलने की खबर है। उन्होंने कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से भी बात की। उन्होंने संसद के सुचारू संचालन और जरूरी विधेयकों को पास कराने में कांग्रेस से सहयोग मांगा। लोकसभा में बुधवार को जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई वैसे ही विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसकी वजह से सदन को स्थगित करना

पड़ा। इसके बाद किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी के चौम्बर में जाकर उनसे मुलाकात की और सहयोग मांगा। हालांकि बताया जा रहा है कि राहुल ने दो टूक शब्दों में कहा कि अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर जब तक चर्चा नहीं होगी और जब तक छात्रों पर हुई कार्रवाई के मामले में अमित शाह का बयान नहीं होगा, तब तक विपक्ष का हंगामा जारी रहेगा। जहां तक महिला आरक्षण और परिसीमन का मामला है तो कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने बताया कि कि किरेन रिजिजू ने बुधवार को परिसीमन के मुद्दे पर उनसे बात की। उन्होंने विचार करके जवाब देने को कहा है। इससे पहले विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी करते हुए गांधी प्रतिमा से मकर द्वार तक मार्च निकाला। विपक्ष के इस हंगामे के बीच सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल राज्यसभा में पास हो गया है। तीन अगस्त को इसे लोकसभा से पास किया गया था। उधर लोकसभा ने बुधवार को बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल, २०२६ को मंजूरी दे दी। यह नया कानून १८६१ के ब्रिटिश शासन के समय बने पुराने कानून की जगह लेगा। इस बिल का मकसद यह है कि बैंकों के डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक, वर्चुअल और क्लाउड में रखे गए रिकॉर्ड भी अदालत में वैध सबूत माने जाएं।

Meta को सरकार की दो टूकः भारत में अमेरिका का कानून नहीं चलेगा

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर अस्थायी रोक लगाने के मामले में सोशल मीडिया कंपनी मेटा को बुलाने के बाद, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना

प्रौद्योगिकी मंत्रालय (**MeitY**) ने गुरुवार को भी कंपनी की भारत आई ग्लोबल टीम से यह सवाल पूछना जारी रखा कि क्या कंपनी भारतीय कानूनों का पालन कर रही है। सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। सूत्रों ने बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को मेटा की ग्लोबल टीम से मुलाकात की, जबकि **MeitY** के अधिकारियों और कंपनी की टेक्निकल टीमों के बीच बातचीत दूसरे दिन भी जारी रही। सरकारी सूत्रों ने कहा कि भारत में काम करने वाले प्लेटफॉर्म सिर्फ अमेरिकी कानूनों के तहत नहीं चल सकते और इन चर्चाओं का मकसद नियमों के पालन से जुड़े तकनीकी पहलुओं को समझना था। सूत्रों ने कहा कि भारत में प्लेटफॉर्म अमेरिकी कानूनों के हिसाब से नहीं चलाए जा सकते। ये तकनीकी मामले हैंय हर पहलू को समझना जरूरी है। मकसद कानून का इस्तेमाल हमारे समाज के फायदे के लिए करना है। सभी संस्थानों की तरह, सभी प्लेटफॉर्म की भी समाज और कानून के प्रति जिम्मेदारी होती है। सूत्रों ने कहा कि मेटा पहले ही सार्वजनिक बयान दे चुका हैय आज तकनीकी जानकारी और लॉग्स पर चर्चा होगी। हम मेटा, **X** और टेलीग्राम जैसे सभी बड़े प्लेटफॉर्म के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। सरकारी सूत्रों ने बताया कि इन बैठकों का मुख्य मकसद यह पता लगाना है कि क्या मेटा के प्लेटफॉर्म भारतीय कानूनों का पालन कर रहे हैं या नहीं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, मेटा से उनके एल्गोरिदम के बारे में भी सवाल पूछे जाएंगे। साथ ही, यह भी देखा जाएगा कि क्या उनके नियमों के पालन की व्यवस्था में जरूरी जांच–पड़ताल और संवैधानिक व कानूनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय मौजूद हैं। प्रधानमंत्री के २३ जुलाई के उस फेसबुक पोस्ट के बाद, जिसमें उन्होंने छात्रों और युवाओं को संबोधित करते हुए परीक्षा के पेपर लीक होने पर सख्त कार्रवाई का वादा किया था, मेटा की ग्लोबल टीम से पूछताछ का यह दूसरा दौर है। इस पोस्ट को प्लेटफॉर्म पर लगभग पाँच घंटे तक रोक दिया गया था, जिससे मध्यस्थ की जवाबदेही को लेकर सवाल उठे थे।

मेटा ने सरकार से माफी मांगी

नई दिल्ली। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोस्ट हटाने के मामले में मेटा ने माफी मांगी है। केंद्र सरकार की ओर से दिए गए अल्टीमेटम पर कंपनी झुकी और उसके सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने सरकार से माफी मांगी। इतना ही नहीं कंपनी ने यह भी माना कि उसके प्लेटफॉर्म पर चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मैटेरियल, डीपफेक और कंटेंट मॉडरेशन से जुड़ी चूक हुई हैं। उसने इसके लिए भी माफी मांगी। सरकार की ओर से अल्टीमेटम देने के बाद बुधवार को मेटा ग्लोबल अफेयर्स के प्रमुख जोएल कैपलन के नेतृत्व में उसकी एक ग्लोबल टीम केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव और आईटी सचिव एस कृष्णन से मिली। गौरतलब है कि फेसबुक ने प्रधानमंत्री मोदी की एक पोस्ट हटा दी थी। सरकार वीडियो फेसबुक से हटाने से भी नाराज थी। इसलिए उसने समन जारी किया और ग्लोबल हेड को माफी मांगने के लिए कहा। असल में मोदी ने २३ जुलाई को यह वीडियो पोस्ट किया था। इसमें उन्होंने पेपर लीक को बड़ी समस्या बताया था। साथ ही ऐसे मामलों की जल्द सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की भी बात कही थी। यह वीडियो कुछ समय के लिए फेसबुक से हटा दिया गया था। बाद में मेटा ने इसे फिर से फेसबुक पर डाल दिया। बहरहाल, बुधवार की बैठक में मेटा ने स्वीकार किया कि कुछ खास तरह के कंटेंट को प्रमोट करने के लिए बड़ी रकम खर्च की गई। इस वजह से प्लेटफॉर्म पर अवैध कंटेंट भी प्रमोट हुआ। बुधवार को हुई बैठक में सरकार ने फेसबुक की पैरेंट कंपनी मेटा से सीएसएएम, डीपफेक, वेरिफाइड अकाउंट्स की सुरक्षा, एल्गोरिद्मिक पक्षपात और भारतीय कानूनों के पालन को लेकर भी जवाब मांगा। जानकार सूत्रों के मुताबिक इन मुद्दों पर आगे भी मेटा के अधिकारियों को फिर बुलाया जाएगा।

सलमान हत्याकांड में नया खुलासा, कोमल बनी विवाद की वजह

सीतापुर। रजत और सलमान के झगड़े में बड़ी वजह कोमल बनी, मारपीट में रजत का पैर टूटने के बाद से ही सलमान को ठिकाने लगाने के योजनाएं बनती रहीं,

हत्या होने के बाद फरार आरोपियों में कुल दस लोगों के शामिल होने की बात सामने आई है। पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पांच अन्य की तलाश में टीमें लखनऊ, खीरी और बहराइच में डेरा डाले हुए हैं। बता दें कि कोतवाली नगर क्षेत्र के मोहल्ला मुंशीगंज निवासी सलमान को बुलाने से पहले उसकी हत्या की जो साजिश रची गई, उसमें शहर के मोहल्ला लोहारबाग निवासी राजा भार्गव उर्फ अभिनव, कोतवाली नगर के रसूलपुर निवासी अभिषेक पुत्र रामचन्द्र और उसकी बहन कोमल कश्यप का हाथ था। बताते हैं कि रजत और सलमान के बीच झगड़े की बड़ी वजह कोमल थी, मारपीट में रजत का पैर भी टूट गया था। क्षेत्राधिकारी नगर कपूर कुमार के मुताबिक, शातिर नितेश त्रिवेदी पुत्र वेद प्रकाश त्रिवेदी निवासी मोहल्ला पूर्णागिरी नगर श्यामनाथ, कोतवाली नगर, मोहम्मद आफाक पुत्र मोहम्मद अल्ताफ निवासी बिजौरा थाना रामकोट जनपद सीतापुर ३. नौशाद पुत्र सत्तार निवासी गदपुरवा थाना मछरेहटा, दीपेन्द्र सिंह उर्फ विक्की पुत्र पप्पल सिंह उर्फ मुखिया निवासी गनेशपुर – कंकरकुई पोस्ट कोटरा थाना बिसवां और सौरभ पुत्र रमेश कुमार निवासी ग्राम रसूलपुर थाना कोतवाली नगर बाइक सहित गिरफ्तार कर लिया गया है। रजत मिश्रा और भैरव मिश्रा का पकड़ा जाना बाकी है। वारदात की साजिश में राजा भार्गव, अभिषेक और उसकी बहन कोमल भी शामिल थीं।

एयर इंडिया को मिला नया सीईओ

नई दिल्ली। एयर इंडिया को नया सीईओ मिल गया है। कैम्पबेल विल्सन की जगह कंपनी ने टेवोल्डे गेब्रेमैरियम को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त किया है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले सीईओ कैंपबेल विल्सन ने इस्तीफा दे दिया था। पिछले कुछ समय से यह विमानन कंपनी घाटे में चल रही है और घाटे से उबरने की रफ्तार भी काफी धीमी है। बहरहाल, टेवोल्डे गेब्रेमैरियम इथियोपिया के बिजनेस एग्जीक्यूटिव हैं। उन्हें अफ्रीका के विमानन उद्योग के सबसे सफल कार्यकारी अधिकारियों में से एक माना जाता है। उन्होंने २०११ से २०२२ तक इथियोपियन एयरलाइंस ग्रुप के ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव अ फिसर के रूप में काम किया था। कोरोना की महामारी के दौरान जब दुनिया भर की विमानन कंपनियां दिवालिया होने की कगार पर थीं और सरकारी वित्तीय पैकेज पर निर्भर थीं, तब टेवोल्डे ने कार्गो यानी माल ढुलाई अ परेशन्स का तेजी से विस्तार किया। इसके दम पर उन्होंने इथियोपियन एयरलाइंस को बिना किसी सरकारी बेलआउट

पैकेज के मुनाफे में बनाए रखा। गौरतलब है कि कैंपबेल विल्सन ने जुलाई २०२२ में एयर इंडिया की कमान संभाली थी। घाटे और कंपनी के सुधार में हो रही देरी के बीच उन्होंने अपने पद से २०२४ में इस्तीफा दे दिया था, जिसे बोर्ड ने स्वीकार कर लिया था। विल्सन नए उत्तराधिकारी की नियुक्ति तक नोटिस पीरियड के दौरान अपने पद पर बने रहे।

चढ़ावा चोरी पर संसद में हंगामा

नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र के तीसरे हफ्ते में भी कामकाज लगातार बाधित हो रहा है। मंगलवार को सत्र के १२वें दिन विपक्षी पार्टियों ने अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में जम कर हंगामा किया। सदन के बाहर संसद परिसर में भी विपक्षी पार्टियों ने चढ़ावा चोरी के मसले पर नारेबाजी की। विपक्ष के हंगामे की वजह से दोनों सदनों में कामकाज ठप्प हुआ। इस हंगामे के बीच ही लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स संशोधन से जुड़ा बिल पेश किया। उधर राज्यसभा में हंगामे के बीच ही जन्म और मृत्यु के पंजीकरण से जुड़ा बिल ध्वनिमत से पास किया गया। मंगलवार को लोकसभा में कई बार स्थगन हुए। कुल मिलाकर सिर्फ २० मिनट सदन चल सका। भोजनावकाश के बाद सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा की कार्यवाही भी दिन में दो बार स्थगित हुई। ११ बजे कार्यवाही

शुरू होने के आधे घंटे के भीतर स्थगित भी हो गई। दोपहर १२ बजे कार्यवाही दोबारा शुरू हुई, लेकिन २० मिनट ही चल पाई। दोपहर दो बजे जब कार्यवाही शुरू हुई तो चढ़ावा चोरी पर जम कर हंगामा हुआ। इससे पहले राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और संसदीय कार्य मंत्री कीरेन रिजिजू के बीच बहस हुई। खड़गे ने कहा, 'राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया था। ट्रस्ट को ७० एकड़ से ज्यादा जमीन सौंपी। पीएम खुद राम मंदिर से जुड़े हर आयोजन में शामिल हुए। अब ईडी, सीबीआई और अन्य केंद्रीय जांच एजेंसियां कहां हैं? सरकार को सदन में इसका जवाब देना चाहिए'। इस पर संसदीय कार्य मंत्री कीरेन रिजिजू ने कहा, 'कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने राम मंदिर बनने पर काली पट्टी बांधकर विरोध किया था। आज वही लोग घड़ियाली आंसू बहाकर देश को गुमराह नहीं कर सकते। पहले भगवान राम का अपमान करने के लिए देश से माफी मांगिए, उसके बाद सरकार से जवाब मांगिए'।

ई–20 पेट्रोल के खिलाफ आप का मार्च

नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सुप्रीम अरविंद केजरीवाल ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल यानी ई–२० पेट्रोल के खिलाफ दिल्ली में मार्च निकाला। उन्होंने 'नेशनल टाउन ह ल' कार्यक्रम में इस मार्च का ऐलान किया था। उनकी पार्टी ने अ नलाइन याचिका के जरिए दो लाख दस्तखत जुटाए हैं। केजरीवाल इसे लेकर प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च करना चाह रहे थे। लेकिन दिल्ली पुलिस ने उनको फिरोजशाह रोड पर ही रोक दिया। इसके बाद केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया और पार्टी के अन्य नेता फिरोजशाह रोड पर ही बीच सड़क पर धरने पर बैठ गए। आम आदमी पार्टी ने करीब एक सौ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ यह मार्च निकाला था। पार्टी का दावा है कि उसने देश भर से २.३० लाख से ज्यादा लोगों की याचिकाएं जुटाई हैं। केजरीवाल ने कहा कि ई–२० पेट्रोल के खिलाफ दो लाख से ज्यादा लोगों ने प्रधानमंत्री को चिट्ठियां लिखी हैं, जिन्हें वे खुद प्रधानमंत्री को सौंपना चाहते थे लेकिन पुलिस ने रोक दिया। इसके बाद केजरीवाल ने कहा, 'हमने सभी चिट्ठियां पुलिस के हाथों मोदी जी को भेज दी हैं'। केजरीवाल ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री को मैसेज भेजा था। उन्होंने कहा, 'हमें उम्मीद है कि पीएम हमसे मिलेंगे'। पुलिस के रोके जाने के बाद धरने पर बैठे अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में मोदी सरकार अमेरिका से इथेन ल खरीद रही है। उन्होंने कहा कि अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा इथेनॉल बनाता है और उसने भारत पर इसे खरीदने का दबाव बनाया। केजरीवाल ने कहा,

'अमेरिका का कचरा खरीदकर हमारी ३० लाख गाड़ियों पर थोपा जा रहा है। इसे रोकने के लिए हमें नीट आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन करना होगा'। केजरीवाल ने लोगों से ई–२० विरोधी अभियान में शामिल होने की अपील करते हुए कहा कि ई–२० नीति के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। आम आदमी पार्टी के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने इसे लेकर कहा, 'हम दो लाख से ज्यादा लोगों की याचिकाएं लेकर आए हैं। हमें आगे जाने दिया जाना चाहिए। अगर कोई दिक्कत है तो प्रधानमंत्री कार्यालय का कोई अधिकारी यहां आकर ज्ञापन ले ले और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हो जाए'। हालांकि पीएमओ का कोई अधिकारी नहीं आया तो चिट्ठियां पुलिस को सौंप दी गईं।

निर्माण की गुणवत्ता को लेकर फिर खड़े हो रहे हैं गंभीर सवाल, उन्नाव में लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस-वे पर फिर धंसी सड़क

उन्नाव। लगभग ४,७०० करोड़ से बने लखनऊ–कानपुर एक्सप्रेस–वे पर निर्माण की गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस एक्सप्रेस–वे पर सड़क धंसने का शुरू हुआ सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि अभी एजेंसी कानपुर से लखनऊ जाने वाली लेन पर मरम्मत करा ही रही थी कि गुरुवार को लखनऊ से कानपुर जाने वाले मार्ग पर भी सड़क धंसने का नया मामला सामने आ गया। मार्ग धंसने की सूचना से कार्यदायी संस्था के कर्मचारी आनन–फानन में वहां पहुंचे और दूसरी लेन पर भी मरम्मत शुरू कराई। लगातार सामने आ रही इन खामियों के कारण वाहन चालकों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई जा रही है। राहगीरों का कहना है कि इतने बड़े बजट की परियोजना में बार–बार सड़क का धंसना घटिया निर्माण व घटिया तकनीक की ओर इशारा करता है। फिलहाल एजेंसी दोनों लेन पर मरम्मत का दावा कर रही है, लेकिन बार–बार आ

रही इन दरारों ने निर्माण की नींव पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। पीएनसी के जनरल मैनेजर सत्या नारायण ने बताया कि हल्की सी दिक्कत आई है। उसकी मरम्मत कराई जा रही है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक बार फिर धंसे एक्सप्रेस–वे को लेकर एक्स पर ट्वीट किया कि 'ये है भाजपाई तरक्कधी की नई हवा...' कुछ दिन पहले ही जिसका उद्घाटन हुआ हो उस सड़क को मरम्मत की जरूरत पड़ गई और मरम्मत को सुखाने के लिए पंखे का इस्तेमाल हो रहा है ये भी हास्यास्पद है। २–३ हफ्ते में ही जिस एक्सप्रेस–वे का दम उखड़ने लगा है उस पर चलने का जोखिम कौन उठाएगा। सवाल ये भी है कि श्अटल प्रोग्रेस वेश योजना में ही रहेगा या कभी बनेगा भी... या कागजों में बनकर उसका शहिस्सा–बांटश हो चुका है। भाजपा राज में हुआ हर निर्माण चलता कम है... धंसता, ढहता, गिरता ज्यादा है। इससे कार्यदायी संस्था की कार्यप्रणाली पर भी उंगलियां उठने लगी हैं। स्थिति यह है कि निर्माण एजेंसी जहां एक ओर दरारों व धंसाव ठीक करने के लिए मरम्मत शुरू कराती है वहीं दूसरी ओर सड़क पर नई खामी उभरकर सामने आ जाती है।

अगले साल आएंगे प्लास्टिक के नोट

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने पॉलीमर यानी प्लास्टिक के नोट छापे जाने की खबरों की पुष्टि कर दी है। रिजर्व बैंक ने बताया है कि प्लास्टिक के नोट अगले साल अप्रैल से मई के बीच लॉन्च होंगे। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी की तीन दिन चली बैठक के बाद आरबीआई केगवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। हालांकि इससे पहले ही यह खबर आ गई थी कि प्लास्टिक के नोट छापने का फैसला हो गया है। संजय मल्होत्रा ने बताया कि शुरुआत में कम वैल्यू के पॉलीमर करेंसी नोट

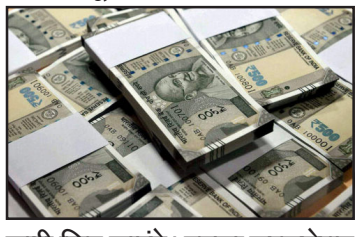

जारी किए जाएंगे। इनका सरकुलेशन और इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। उन्होंने कहा, 'दुनिया के कई देशों जैसे ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में पॉलीमर करेंसी नोट ३० साल से भी अधिक समय तक सफलतापूर्वक उपयोग में रहे हैं। भारत में कागजी नोट, खास कर १०, २० और ५० रुपए के छोटे नोट, बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं या फटने लगते हैं। गवर्नर ने कहा, 'पॉलीमर नोट आने से इनकी उम्र बढ़ेगी, पानी या नमी से ये खराब नहीं होंगे और बार बार नए नोट छापने का सरकारी खर्च भी कम होगा'।

इटौंजा–देवा–चिनहट फोरलेन परियोजना ने पकड़ी रफ्तार, मकानों–दुकानों पर शुरू हुई निशानदेही

देवा। इटौंजा से कुर्सी, देवा होते हुए लखनऊ के चिनहट तक प्रस्तावित फोरलेन सड़क परियोजना अब तेजी से धरातल पर उतरने लगी है। गुरुवार को राजस्व विभाग और लोक निर्माण विभाग की संयुक्त टीम ने सड़क चौड़ीकरण की जद में आने वाले मकानों, दुकानों और अन्य निर्माणों पर नंबर अंकित कर उन्हें चिन्हित किया। यह कार्रवाई सड़क निर्माण से पहले प्रभावित परिसंपत्तियों का अंतिम सत्यापन और आगे की प्रक्रिया पूरी करने के लिए की गई। करीब ४६४ करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना के तहत पूरे मार्ग को २५ मीटर चौड़ा फोरलेन बनाया जाएगा। परियोजना पर लगभग १८० करोड़ रुपये सड़क निर्माण, १५० करोड़ रुपये इंदिरा नहर पर दो फोरलेन पुलों के निर्माण तथा शेष धनराशि बिजली के खंभों, पेड़ों और अन्य अवरोधों को हटाने एवं स्थानांतरित करने पर खर्च की

जाएगी परियोजना के तहत इंदिरा नहर पर दो नए फोरलेन पुल बनाए जाएंगे। इनमें एक पुल माती के पास तथा दूसरा कुर्सी के निकट प्रस्तावित है। पुलों के निर्माण से मार्ग पर यातायात अधिक सुरक्षित और सुगम होगा गुरुवार को विभागीय टीम ने सड़क के दोनों ओर स्थित प्रभावित भवनों का मौके पर सत्यापन कर उन पर नंबर अंकित किए। इसके बाद नियमानुसार मुआवजा और ध वस्तीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। दूसरी ओर, सड़क निर्माण के लिए मार्ग किनारे खड़े पेड़ों की कटाई का कार्य पहले से ही शुरू हो चुका है, जिससे परियोजना के काम में तेजी आने के संकेत हैं फोरलेन बनने के बाद इटौंजा, कुर्सी, देवा और चिनहट के बीच आवागमन अधिक सुगम होगा। इससे जाम की समस्या में कमी आएगी और बाराबंकी, लखनऊ तथा आसपास के क्षेत्रों के बीच संपर्क बेहतर होने के साथ औद्योगिक, व्यापारिक और धार्मिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। राजस्व निरीक्षक देवा शिवकुमार ने बताया कि सड़क चौड़ीकरण की जद में आने वाले भवनों और अन्य निर्माणों की निशानदेही की जा रही है। चिन्हांकन की कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है और आगे की प्रक्रिया संबंधित विभागों द्वारा पूरी की जाएगी। लोक निर्माण विभाग के अवर अभियंता माता प्रसाद यादव के मुताबिक फोरलेन परियोजना के तहत सड़क को २५ मीटर चौड़ा बनाया जाएगा। पेड़ों की कटाई का कार्य शुरू हो चुका है और चिन्हांकन के बाद आगे की निर्माण संबंधी प्रक्रिया निर्धारित योजना के अनुसार तेजी से आगे बढ़ाई जाएगी।

गाड़ी कैसे पलटाई गई समय आने पर पता चल जाएगा जब 'सैटेलाइट इमेज' निकाली जाएगी : अखिलेश

लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ में जनेश्वर मिश्र की जयंती पर आयोजित ब्राह्मण मंच के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सपा मुखिया अखिलेश यादव को कानपुर के विकास दुबे याद आ गया। बिना किसी नाम का जिक्र करते उन्होंने कहा कि याद होगा जब गाड़ी पलटी थी, वह गाड़ी नहीं पलटी थी, बल्कि सरकार पलटने से बच गई थी। अखिलेश ने कहा कि समय आने पर जब 'सैटेलाइट इमेज' निकाली जाएगी, तब पता चलेगा कि गाड़ी कैसे पलटाई गई थी। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि पहले सपा कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा था, लेकिन अब ब्राह्मण समाज को भी निशाना बनाया जा रहा है। इससे पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि जनेश्वर मिश्र ऐसे समाजवादी चिंतक थे जिन्होंने जीवनभर समाजवादी सिद्धांतों को अपनाया और बिना किसी भेदभाव के सभी को जोड़ने का काम किया। उन्होंने सपा सांसद सनातन पांडेय और उनके सहयोगियों का स्वागत करते

हुए कहा कि वे प्रदेश के कई जिलों में पहुंचे और आज का बड़ा कार्यक्रम उसी का परिणाम है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि जहां इस कार्यक्रम की अनुमति मिलनी चाहिए थी, वहां प्रशासन ने परमिशन नहीं दी, इसलिए कार्यक्रम दूसरे स्थान पर करना पड़ा, लेकिन उनका मिशन रुकने वाला नहीं है। पीडीए (PDA) को लेकर उन्होंने कहा कि 'पी' का मतलब पंडित भी है और पीड़ित भी। उन्होंने कहा कि जो लोग पीडीए से हार गए हैं, वहीं इसकी अलग-अलग परिभाषाएं गढ़ रहे हैं। उनके मुताबिक, 'पीडीए में पी का मतलब पीड़ित है। जितनी पीड़ा दोगे, पीडीए उतना ही मजबूत होगा।' अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि श्एक डीसीएम हैं, उनकी कोई गार्ड नहीं सुनता। लोग यह नहीं जानते कि गार्ड की बात गार्ड कैसे सुनेगा।श उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि आज स्वास्थ्य विभाग को ही इलाज की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने सामाजिक व्यवस्था पर टिप्पणी करते हुए कहा कि 'केवल एक घटना की बात नहीं है, सब लोग जानते हैं कि हम कितनी भी डिग्री हासिल कर लें, शंकराचार्य नहीं बन सकते।'

मेरा रेशम, मेरा अभिमान २.० अभियान से जुड़े किसान, वैज्ञानिकों ने बताए आय बढ़ाने के आधुनिक तरीके

मितौली खीरी। केंद्रीय रेशम बोर्ड की महत्वाकांक्षी योजना मेरा रेशम मेरा अभिमान २.० के तहत राजकीय रेशम फार्म शाहपुर जागीर में रेशम उत्पादक किसानों के लिए एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लेकर रेशम की आधुनिक एवं वैज्ञानिक खेती की तकनीकों की जानकारी प्राप्त की।कार्यक्रम में केंद्रीय रेशम बोर्ड (सीएसआर टीआई, पम्पोर) के वैज्ञानिकों एवं तकनीकी विशेषज्ञों ने किसानों को शहतूत की उन्नत खेती, जल एवं पोषक तत्व प्रबंधन, वैज्ञानिक तरीके से रेशम कीट पालन, लेट एज रियरिंग तथा रोग एवं कीट प्रबंधन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। विशेषज्ञों ने बताया कि वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाकर किसान कम लागत में अधिक एवं गुणवत्तापूर्ण कोषा उत्पादन कर अपनी आय में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकते हैं। इस अवसर पर केंद्रीय रेशम बोर्ड के वैज्ञानिक विपिन कुमार, तकनीकी विशेषज्ञ आशीष कुमार, राज्य रेशम विभाग के अधिकारी महेंद्र शंकर, शाहपुर जागीर के ग्राम प्रधान एडवोकेट अजीत सिंह तथा मीडिया प्रतिनिधि गौरव सिंह मौजूद रहे। अतिथियों ने कहा कि

रेशम उत्पादन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने का प्रभावी माध्यम है और सरकार किसानों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।कार्यक्रम के दौरान किसानों ने रेशम उत्पादन से जुड़े विभिन्न प्रश्न पूछे, जिनका विशेषज्ञों ने विस्तारपूर्वक समाधान किया तथा भविष्य में भी तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया। कार्यक्रम के समापन पर किसानों ने वैज्ञानिक विधियों को अपनाकर रेशम उत्पादन बढ़ाने और आत्मनिर्भर बनने का संकल्प लिया।

बाढ़ व जलभराव से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर ४१ बाढ़ चौकियां और १४ सचल चिकित्सा दल तैनात

लखीमपुर–खीरी। बाढ़ एवं जलभराव से प्रभावित जनमानस को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। वर्तमान में जनपद के ६ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाढ़ एवं जलभराव से प्रभावित होते हैं जिन पर बाढ़ को लेकर तैयारी की गई है यहां मेडिकल टीम सहित अतिरिक्त इमरजेंसी दवाओं की व्यवस्था भी की गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ संतोष गुप्ता द्वारा बताया गया कि जिले में बाढ़ नियंत्रण के लिए ४१ बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं, जिनमें ३२ अधिकारियों तथा १४० कर्मचारियों की तैनाती कर उन्हें सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। जनपद की ५ तहसीलों (लखीमपुर, पलिया, गोला, निघासन व धौरहरा) के ६ प्रभावित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (नकहा, पलिया, निघासन, धौरहरा, बिजुआ, खमरियाधईसानगर, फूलबेहड़, रमियाबेहड़ व गोला) पर त्वरित उपचार हेतु रैपिड रिस्पॉन्स टीम (RRT) का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रभावित क्षेत्रों के लिए १४ सचल चिकित्सीय दल गठित किए गए हैं। दिनांक ०५ अगस्त २०२६ तक प्रभावित बाढ़ चौकी ग्रांट नं० १२ (फूलबेहड़) के ग्राम में कुल ६७० प्रभावित जनसंख्या में से २४७ मरीजों का उपचार किया जा चुका है तथा १३३६ क्लोरीन टैबलेट व ६५७ ओआरएस पैकेट वितरित किए गए हैं। जिले में सर्पदंश से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बाढ़ प्रभावित सीएचसी पर आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से वितरण हेतु मेडिसिन किट, ओआरएस पैकेट व क्लोरीन टैबलेट उपलब्ध करा दी गई हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में २४ घंटे ७ दिन संचालित बाढ़ एवं संक्रामक रोग कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। सभी सीएचसी और केंद्रीय औषधि भंडार में जीवन रक्षक दवाओं के साथ-साथ एंटी स्नेक वेनम एवं एंटी रैबीज वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। साथ ही, १०८ और १०२ एम्बुलेंस सेवाओं को २४ घंटे सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी व कर्मचारी प्रभावित ग्रामीणों के इलाज के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित हैं।

वर्दी के रौब में महिला सिपाही ने रोका आम रास्ता, विरोध करने पर मोहल्ले वालों को दी भुगतने की धमकी

लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश पुलिस की एक महिला सिपाही पर अपने पद और वर्दी का धौंस दिखाकर आम रास्ता बाधित करने और स्थानीय निवासियों से अभद्र व्यवहार करने का गंभीर आरोप लगा है।मामला कोतवाली सदर इलाके के मोहल्ला राजाजीपुरम निकट अनुपम नर्सिंग होम,रांची वाली गली का है।पीड़ित स्थानीय निवासी सेवकलाल ने इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सदर को सम्बोधित एक शिकायत ४००१५३२६०४१६७१ से पीड़ित ने सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर अ नलाइन करके कार्रवाई करने की मांग की है और शिकायत पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। शिकायतकर्ता सेवकलाल के मुताबिक, उनके पड़ोस में स्थित मिथिलेश सिंह के मकान में दिव्या नाम की एक महिला सिपाही किराए पर रहती हैं।आरोप है कि उक्त महिला सिपाही और उनके साथ आने वाले अन्य पुलिसकर्मी अपनी गाड़ियों को पूरी गली और आम रास्ते पर आड़ा-तिरछा खड़ा कर देते हैं।इसके कारण पूरी गली घिर जाती है और वहां के स्थानीय निवासियों तथा राहगीरों का निकलना तक दूभर हो जाता है। विरोध करने पर गाली-गलौज और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी पीड़ित का आरोप है कि जब भी स्थानीय लोग या राहगीर गाड़ियों को किनारे लगाने का अनुरोध करते हैं, तो महिला सिपाही और उनके सहकर्मी अपने पुलिस पद का रौब दिखाने लगते हैं।सेवकलाल ने बताया कि रास्ते से गाड़ी हटाने की बात कहने पर उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया अपशब्द कहे गए और पुलिसिया धौंस दिखाते हुए गंभीर परिणाम भुगतने की धमकियां दी गईं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह कृत्य सार्वजनिक शांति को भंग करने वाला और पुलिस विभाग की छवि को धूमिल करने वाला है। पीड़ित सेवकलाल ने बताया कि उन्होंने इस मामले को लेकर सबसे पहले २६ जुलाई २०२६ को राजापुर पुलिस चौकी प्रभारी को लिखित शिकायती पत्र दिया था। लेकिन एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी चौकी पुलिस द्वारा इस पर कोई जांच या कार्रवाई नहीं की गई। चौकी स्तर पर सुनवाई न होने से परेशान होकर पीड़ित ने अब कोतवाली सदर के प्रभारी निरीक्षक को पत्र भेजकर मामले की निष्पक्ष जांच कराने, आम रास्ते से अवैध पार्किंग हटवाने और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ विधिक व विभागीय कार्रवाई करने की मांग की है।

जिला भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ मनाया विधान परिषद सदस्य अनूप गुप्ता का जन्मदिन

लखीमपुर–खीरी।भारतीय जनता पार्टी के निर्वतमान प्रदेश महामंत्री एवं उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्य अनूप गुप्ता का जन्मदिन गुरुवार को जिले में सेवा, समर्पण और सामाजिक सरोकार की भावना के साथ धूमधाम से मनाया गया। भाजपा जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर वृद्धजनों, दिव्यांग बच्चों और स्कूली विद्यार्थियों के साथ जन्मदिन की खुशियां साझा कीं। इस दौरान केक काटा गया, उपहार वितरित किए गए और सभी ने अनूप गुप्ता के स्वस्थ, दीर्घायु एवं यशस्वी जीवन की कामना की। कार्यक्रम की शुरुआत वृद्धाश्रम से हुई, जहां भाजपा जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने वृद्धजनों के बीच पांच किलोग्राम का केक काटकर जन्मदिन मनाया। सभी बुजुर्गों का सम्मान किया गया और उनके साथ आत्मीयता से समय बिताते हुए उन्हें मिठाई वितरित की गई। इसके बाद कार्यकर्ताओं का कारवां कारवां मूक-बधिर विद्यालय पहुंचा, जहां विशेष बच्चों के साथ केक काटकर जन्मदिन की खुशियां साझा की गईं। बच्चों को उपहार भेंट किए गए और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई।इसके उपरांत मिदनियाँ गढ़ी उच्च प्राथमिक विद्यालय परिसर में भी अनूप गुप्ता का जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। विद्यालय के छात्र-छात्राओं के साथ केक काटा गया तथा उन्हें उपहार वितरित किए गए। बच्चों ने भी पूरे उत्साह के साथ कार्यक्रम में भाग लिया और जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं।इस अवसर पर ग्राम प्रधान अनुश्री जायसवाल, प्रधान प्रतिनिधि मनोज जायसवाल, बूथ अध्यक्ष आदित्य बारी, रामकिशन श्रीवास्तव, प्रधानाचार्य अनिल प्रताप सिंह, समस्त अध्यापकगण तथा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने अनूप गुप्ता के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और निरंतर जनसेवा के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि समाज के प्रत्येक वर्ग के साथ जुड़कर खुशियां बांटना प्रेरणादायी कार्य है। पूरे कार्यक्रम का वातावरण उत्साह, आत्मीयता और सेवा भावना से ओत-प्रोत रहा।

यूपी में परिवहन प्रवर्तन होगा और मजबूतः पांच जिलों में डंपिंग यार्ड निर्माण के लिए ६.०३ करोड़ मंजूर

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवहन विभाग की प्रवर्तन व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश के बुलंदशहर, शामली, शाहजहांपुर, पीलीभीत और बाराबंकी में डिटेंशन (डंपिंग) यार्ड के निर्माण के लिए ६.०३ करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। बाराबंकी, पीलीभीत और शाहजहांपुर के लिए दूसरी एवं अंतिम किश्त के रूप में क्रमशः १.६२ करोड़, १.४४ करोड़ और १.३४ करोड़ की स्वीकृति दी गई है। इसमें मिट्टी भराई के लिए भी धनराशि शामिल है। स्वीकृत राशि कार्यदायी संस्था सीएनडीएस को जारी की जा रही है। इसके अलावा लखनऊ और औरैया में भी डिटेंशन यार्ड निर्माण की प्रक्रिया तेज हो गई है। दोनों जिलों में निःशुल्क भूमि उपलब्ध होने के बाद क्रमशः

२.५५ करोड़ और ४.०७ करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी गई है। वहीं उन्नाव और अलीगढ़ में भी भूमि उपलब्ध होने के बाद परियोजना का आगणन तैयार कर शासन को भेजने की प्रक्रिया जारी है। अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) केडी सिंह गौर ने बताया कि कई जनपदों में जब्त वाहनों को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं होने से प्रवर्तन कार्रवाई प्रभावित होती है। डिटेंशन यार्ड बनने के बाद वाहनों की सुरक्षित अभिरक्षा, निगरानी और रिकॉर्ड प्रबंधन बेहतर होगा तथा परिवहन विभाग की कार्रवाई अधिक प्रभावी और व्यवस्थित तरीके से संचालित की जा सकेगी। परिवहन विभाग के अनुसार, इन यार्डों के निर्माण से प्रवर्तन कार्रवाई के दौरान जब्त या रोके गए वाहनों को सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से रखने की सुविधा मिलेगी। इससे थानों में जगह की कमी की समस्या कम होगी और कार्रवाई अधिक प्रभावी ढंग से संचालित की जा सकेगी।

पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले बर्खास्त सिपाही सुनील को राहत

लखनऊ। पुलिस विभाग के बड़े अफसरों पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व आरक्षी सुनील

कुमार शुक्ला की सेवा से बर्खास्तगी को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई हुई है। यह सुनवाई लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण में हुई है, प्रारम्भिक सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर अपना उत्तर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। मामले की सुनवाई रवीन्द्र नाथ त्रिपाठी, सदस्य (न्यायिक) एवं सुखलाल भारती, सदस्य (प्रशासनिक) की पीठ के समक्ष हुई। इस मामले में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता डॉ. नूतन ठाकुर एवं अधिवक्ता दीपक कुमार हैं। याचिका में सुनील कुमार शुक्ला की बर्खास्तगी को तथ्य एवं विधि दोनों दृष्टियों से असंवैधानिक एवं अवैध बताते हुए उसे निरस्त करने, सेवा में पुनर्स्थापना तथा अन्य सभी विधिसम्मत सेवा लाभ प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया है। याचिका का प्रमुख आधार यह है कि याचिकाकर्ता की सेवाएँ भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३११(२) के द्वितीय प्रावधान का सहारा लेकर समाप्त की गईं, जबकि याचिकाकर्ता के अनुसार इस मामले में इस संवैधानिक प्रावधान का प्रयोग विधिसम्मत नहीं था। इसके परिणामस्वरूप उन्हें नियमित विभागीय जांच तथा अपना पक्ष रखने का संवैधानिक अवसर प्राप्त नहीं हो सका। याचिका में यह भी कहा गया है कि सुनील कुमार शुक्ला द्वारा पुलिस विभाग में कथित भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के संबंध में सार्वजनिक रूप से आवाज उठाने के बाद उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की गई और अंततः उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।

अहमदाबाद में 'बंटवारा १९४७' के प्रमोशन में जुटे सनी देओल

मुम्बई। बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल, करण देओल और अभिनेत्री प्रीति जिंटा अपनी आगामी फिल्म 'बंटवारा १९४७' के प्रचार के सिलसिले में अहमदाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने छात्रों, प्रशंसकों और मीडिया से मुलाकात की तथा गुजराती थाली का स्वाद लिया। आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी इस फिल्म का निर्देशन राजकुमार संतोषी ने किया है। फिल्म १४ अगस्त को विश्वभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म का ट्रेलर २८ जुलाई को जारी किया गया था, जिसे दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। प्रचार अभियान के तहत सनी देओल, करण देओल और प्रीति जिंटा ने अहमदाबाद में साबरमती रिवरफ्रंट का दौरा किया। इसके बाद तीनों सिल्वर ओक यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां उन्होंने छात्रों और प्रशंसकों से

बातचीत की। बाद में उन्होंने एक रेस्तरां में मीडिया के साथ गुजराती थाली का आनंद लिया और फिल्म को लेकर चर्चा की। 'बंटवारा १९४७' भारत के विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित एक भावनात्मक कहानी है, जिसमें प्रेम, त्याग, साहस और मानवीय रिश्तों को केंद्र में रखा गया है। फिल्म में शबाना आजमी, सनी देओल, प्रीति जिंटा, करण देओल, अली फजल और अभिमन्यु सिंह प्रमुख भूमिकाओं में हैं। करीब तीन दशक बाद निर्देशक राजकुमार संतोषी और सनी देओल की जोड़ी इस फिल्म के माध्यम से फिर साथ आई है। फिल्म का संगीत ए. आर. रहमान ने तैयार किया है, जबकि गीत जावेद अख्तर ने लिखे हैं। फिल्म का निर्माण आमिर खान और अपर्णा पुरोहित ने किया है। 'बंटवारा १९४७' १४ अगस्त २०२६ को दुनियाभर के सिनेमाघरों में प्रदर्शित होगी।

अभिनेता प्रदीप सिंह रावत को नम आंखों से अंतिम विदाई

मुंबई। 'सरफरोश', 'लगान' और 'गजनी' जैसी लोकप्रिय हिंदी फिल्मों में दमदार अभियान के लिए पहचाने जाने वाले अभिनेता प्रदीप रावत का अंतिम संस्कार बुधवार यानी आज शाम यहां किया जाएगा। कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद रावत का मंगलवार को मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया था। वह ७४ वर्ष के थे। अभिनेता प्रदीप सिंह रावत को बुधवार को मुंबई में नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। उनका अंतिम संस्कार गोरेगांव के ओशिवारा श्मशान घाट में परिवार, दोस्तों और फिल्म इंडस्ट्री की कई हस्तियों की मौजूदगी में संपन्न हुआ।प्रदीप सिंह रावत का मंगलवार देर शाम कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में निधन हो गया था। उनके परिवार में पत्नी कल्याणी रावत और पुत्र विक्रमादित्य हैं। उत्तराखंड में जन्मे प्रदीप सिंह रावत ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत रंगमंच से की। थिएटर में लंबे अनुभव ने उनकी दमदार संवाद अदायगी और प्रभावशाली स्क्रीन प्रेजेंस को नई पहचान दिलाई। उन्होंने छोटे पर्दे पर बी.आर. चोपड़ा के लोकप्रिय धारावाहिक 'महाभारत' में अश्वत्थामा की भूमिका निभाकर घर–घर पहचान बनाई। इसके बाद उन्होंने हिंदी के साथ–साथ तमिल, कन्नड़, मलयालम, बंगाहिंदी फिल्मों के साथ–साथ उन्होंने दक्षिण भारतीय सिनेमा और टेलीविजन धारावाहिकों से भी पहचान बनायी। रावत के मित्र और अभिनेता दया शंकर पांडेय ने कहा, ''दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग में उनकी पहचान अमरीश पुरी जैसी थी। उन्होंने ४०० से अधिक फिल्मों में काम किया था। प्रदीप का व्यक्तित्व बेहद प्रभावशाली था।'' फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर प्रदीप रावत के अंतिम संस्कार की जानकारी दी और उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने लिखा, ''हमारे प्रिय मित्र, शानदार अभिनेता और बेहतरीन इंसान प्रदीप रावत के कैंसर के कारण निधन की खबर से बेहद दुखी और

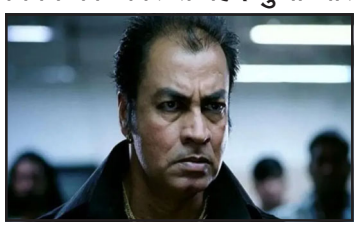

स्तब्ध हूं। यह फिल्म उद्योग के लिए अपूरणीय क्षति है। उनके परिवार और करीबियों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं।'' उन्होंने कहा, ''आज शाम चार बजे तक उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए गोरेगांव पश्चिम स्थित बी–विंग, पी–३, इम्पीरियल हाइट्स में रखा जाएगा। इसके बाद शाम चार बजे उनका पार्थिव शरीर जोगेश्वरी पश्चिम में एस.वी. रोड स्थित ओशिवारा पुल के पास अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा।'' प्रदीप रावत को पहली बड़ी पहचान धारावाहिक 'महाभारत' में अश्वत्थामा की भूमिका निभाकर मिली। इसके बाद उन्होंने 'तहकीकात', 'चंद्रकांता' और 'युग' जैसे लोकप्रिय टीवी धारावाहिकों में भी अभिनय किया। उनकी प्रमुख हिंदी फिल्मों में 'अग्निपथ', 'मेरी जंग', 'सरफरोश', 'द हीरोः लव स्टोरी ऑफ ए स्पाई' और 'छावा' शामिल हैं। दक्षिण भारतीय सिनेमा में प्रदीप रावत को विशेष रूप से खलनायक की भूमिकाओं के लिए सराहा गया। 'साई, 'मंगला' और 'नायक' जैसी फिल्मों में खलनायक के रूप में उनके किरदारों को काफी प्रशंसा मिली। उन्होंने सूर्या अभिनीत तमिल फिल्म 'गजनी' में भी खलनायक की भूमिका निभायी और बाद में आमिर खान अभिनीत इसके हिंदी रीमेक 'गजनी' में भी यही किरदार निभाया।

हमारे अन्य प्रतिनिधि
संजय बाजपेई
सीतापुर
मो.9935160370
प्रियंका त्रिपाठी
नई दिल्ली
विधिक सलाहकार
सुरेश नारायण मिश्र
क्षेत्रीय सम्पादक
सौरभ कुमार, बिहार
मो.09386075289
मो० अरशद
ब्यूरो चीफ
मऊ

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक आरती पाण्डेय द्वारा सांई आफसेट प्रिन्टर्स, 40 वासुदेव भवन भातखण्डे संगीत महाविद्यालय के पीछे, कैसरबाग लखनऊ से छपवाकर एमआईजी 2/379 रश्मिखंड शारदानगर आशियाना लखनऊ उ0प्र0 से प्रकाशित।
आर.एन.आई
UPHIN/2010/32566
सम्पादक
आरती पाण्डेय
मो.9415087228
9889745884. 9807059191. 9026560178
Email-
adbhutsamachar@yahoo.in
adbhut_samachar@rediffmail.com
सभी विवादों का न्यायक्षेत्र लखनऊ होगा।

समाचार पत्र में छपी समस्त प्रकार की खबरों एवं लेखों का स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक आरती पाण्डेय से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। समाचार पत्र में छपी खबर एवं लेख पत्रकारों के अपने निजी विचार हैं। समाचार पत्र से जुड़े समस्त पत्रकारों के पद अवैतनिक हैं। और वह सब स्वतंत्र पत्रकार हैं। प्रकाशक/सम्पादक